डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 जून, 2020, डिस्पेच दिनांक 16 जून, 2020

| वर्ष 64 | अंक 02 | भोपाल | 16 जून, 2020 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

प्रदेश में एकल नागरिक डाटाबेस बनाया जाएगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एकल नागरिक डाटाबेस संबंधी बैठक ली

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में शीघ्र ही एकल नागरिक डाटाबेस तैयार किये जाने का कार्य किया जाएगा। अभी विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए नागरिकों से बार-बार जानकारी मांगनी पड़ती है। एकल नागरिक डाटाबेस बन जाने से नागरिकों को बार-बार जानकारी नहीं देनी होगी। शासन के पास उपलब्ध जानकारी का विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में प्रदेश में एकल नागरिक डाटाबेस तैयार किए जाने संबंधी बैठक ले रहे थे।

वर्तमान में अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग पंजीयन

प्रदेश में वर्तमान में लगभग 600 से 700 हितग्राहीमूलक योजनाएँ संचालित होती है। इन योजनाओं का लाभ देने के लिए हितग्राहियों का अलग-अलग पंजीयन किया जाता है। इससे एक ओर शासकीय मशीनरी को बहुत समय खर्च करना पड़ता है वहीं नागरिकों को भी बार-बार जानकारी उपलब्ध करानी होती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि एकल नागरिक डाटाबेस बन जाने से शासकीय मशीनरी का समय बचेगा, वहीं नागरिकों के लिए नई व्यवस्था अधिक सुविधाजनक होगी।

राजस्थान, आंध्रप्रदेश व तेलंगाना में व्यवस्था लागू

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान, तेलंगाना एवं आंध्रप्रदेश राज्यों में नागरिक डाटाबेस बनाया गया है। राजस्थान में यह योजना **भामाशाह** के नाम से तथा आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना में **प्रजा साधिकार** नाम से संचालित है।

बार-बार नहीं मांगने होंगे दस्तावेज

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि एकल नागरिक डाटाबेस बन जाने से हितग्राहियों से बार-बार उनके दस्तावेज नहीं मांगने होंगे। जैसे एक बार किसी नागरिक का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद उसका रिकार्ड एकल डाटाबेस में रहेगा, अतः किसी दूसरी योजना का लाभ लेने के लिए उससे दोबारा जाति प्रमाण पत्र मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।

ये जानकारियाँ रहेंगी

एकल नागरिक डाटाबेस में नागरिक के नाम, पते आदि के अलावा उसकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि का विवरण, उगाई गई फसल, मूल निवासी प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र आदि की जानकारी रहेगी।

एकल डाटाबेस का निर्माण

एकल डाटाबेस के निर्माण के लिए समग्र डाटा को बेहतर बनाया जाएगा तथा आधार के बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रकार के डाटा का मिलान कर तथा नागरिक का बायोमेट्रिक्स सत्यापन कर एकल डाटाबेस का निर्माण किया जाएगा। इसे निरंतर अपडेट करने की व्यवस्था भी की जाएगी।

गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुंचा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने टीम और किसानों को दी बधाई

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को गेहूँ उपार्जन में देश में प्रथम स्थान अर्जित करने पर खाद्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने उपार्जन की विभिन्न गतिविधियों के छायाचित्रों के कोलांज का मोमेन्टो भेंट किया।

भोपाल। मसमर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुँच गया है। मध्यप्रदेश में अभी तक 1 करोड़ 27 लाख 67 हजार 628 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है। पंजाब दूसरे स्थान पर है। देश के सभी राज्यों द्वारा कुल उपार्जन गेहूँ का 33 प्रतिशत मध्यप्रदेश में उपार्जन किया गया है। पूरे देश में 3 करोड़ 86 लाख 54 हजार मेट्रिक टन गेहँ का उपर्जान किया गया है। गत वर्ष की तुलना में मध्यप्रदेश में गेहूँ उपार्जन में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष मध्यप्रदेश में 73.69 लाख गेहूँ का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया था।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूँ उपार्जन के प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने 23 मार्च से लगातार 75 बैठकें कर गेहूँ उपार्जन की प्रतिदिन समीक्षा की। कोरोना लॉकाडाउन एवं निसर्ग तूफान के अवरोध को पीछे छोड़ते हुए उपार्जन कार्य में लगा अमला कोरोना योद्धा और मध्यप्रदेश के किसान कोरोना विजेता सिद्ध हुए है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस उपलब्धि के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम और प्रदेश के किसानों को बधाई दी है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

सूचना

कोविड-19 के कारण हुए लाकडाउन की वजह से मध्यप्रदेश सहकारी समाचार के अंक 21 से 23 तक प्रकाशित नहीं हो पाये। अंक 24 व 1 ई-सहकारी समाचार के रूप में प्रकाशित किये गये थे। इस अंक से नियमित सहकारी समाचार प्रकाशित किया जा रहा है।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान जारी

भोपाल। मप्रदेश के 32 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहकों को संग्रहण वर्ष 2018 में संग्रहीत तेन्दूपत्ते के शुद्व लाभ से 183 करोड़ 94 लाख के प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मई से संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण का कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ तेन्दूपत्ता के व्यवसाय से होने वाली सम्पूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में शुद्व आय का 70 प्रतिशत भाग संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहीत मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नगद भुगतान किया जाता है। शेष 30 प्रतिशत में से 15 प्रतिशत भाग वनों के पुनरुत्पादन और 15 प्रतिशत अवशेष राशि सहकारी समितियों को उनकी प्राथमिकता और माँग के आधार पर गाँव की मूलभूत सुविधाओं के विकास में व्यय किया जाता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नगरीय निकायों को 330 करोड़ रूपये अंतरित किए सिंगल क्लिक से

शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना एवं पथ विक्रेता पोर्टल का शुभारंभ किया

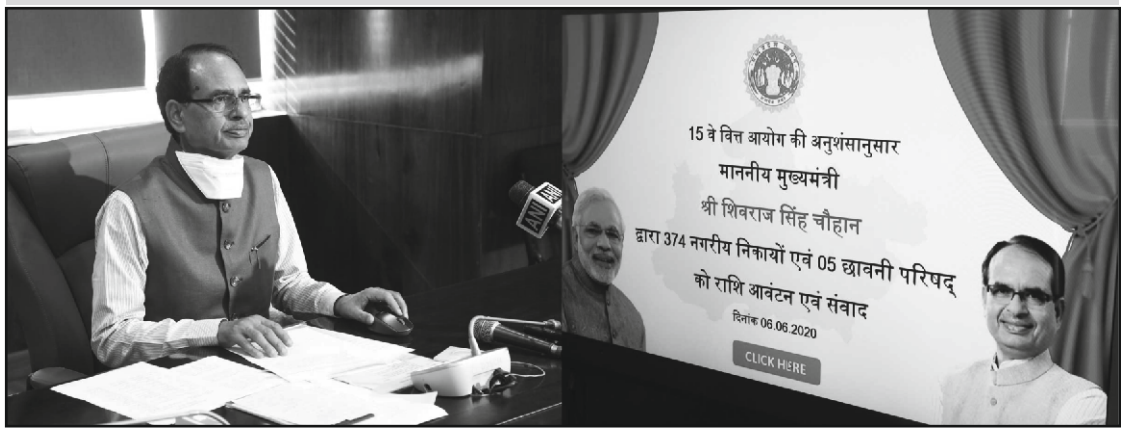

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से प्रदेश के 374 नगरीय निकायों एवं 5 छावनी परिषदों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 330 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की। उन्होंने शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना एवं शहरी पथ विक्रेता पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री नीतेश व्यास, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि आदि उपस्थित थे।

शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के पथ विक्रेताओं को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत के यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत शहरी पथ व्यवसायियों को 10 हजार रूपये का ऋण दिया जायेगा। इसमें 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान सहायता केन्द्र सरकार देगी। मध्यप्रदेश सरकार ने इसी के साथ शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत शेष ब्याज की राशि, जो लगभग 5 प्रतिशत होगी, राज्य सरकार भरेगी। इस प्रकार हितग्राही को 10 हजार रूपये का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा। इसकी गारंटी सरकार देगी।

पोर्टल पर पंजीयन अवश्य करवायें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पथ विक्रेताओं/व्यवसायियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिए जाने के उद्देश्य शहरी पथ विक्रेता पोर्टल भी प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत शहरी असंगठित कामगारों – सड़क पर, पथ पर, गुमठी लगाकर, ठेला चलाकर व्यवसाय करने वालों का पोर्टल पर पंजीयन किया जायेगा। यह एकीकृत पोर्टल उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ देगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पथ विक्रेताओं से आग्रह किया कि वे इस पोर्टल पर अपना पंजीयन अवश्य करवायें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीसी के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के पथ विक्रेताओं भोपाल के मुनेश (चाट ठेला), संजय कुशवाह (सब्जी ठेला), उज्जैन की अनीता जैन (सब्जी ठेला), नरेन्द्र सिंह वैश्य (सब्जी ठेला), सतना की शीला कुशवाह (सब्जी विक्रेता), प्रमोद सोनी (पथ विक्रेता), इंदौर की बबीता (सब्जी पथ विक्रेता), अमरजी (सब्जी व्यवसाय) तथा दतिया के शिवराज सिंह (ताला–चाबी ठेला), कौशल्या पाल (फल ठेला) आदि से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दी गई राशि से वे अपना व्यवसाय करें। प्रसन्न रहें। मध्यप्रदेश सरकार हमेशा आपके साथ है।

नगरीय निकाय दी गई राशि से करा सकेंगे विभिन्न कार्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि नगरीय निकायों को दी गई 330 करोड़ रूपये की राशि से पेयजल व्यवस्था, नाली निर्माण, सीवरेज कार्य, सड़क निर्माण, सड़क मरम्मत, अधोसंरचना विकास, गंदी बस्ती विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाओं आदि से संबंधित कार्य करा सकेंगे।

उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाये।
– स्वामी विवेकानंद

सी.एम. हेल्पलाइन से आठ लाख से अधिक लोगों को मिली सहायता

भोपाल। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान आमजन को सहज रूप से उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की वजह से सी.एम. हेल्पलाईन 181 में आने वाली शिकायतें, जरूरतें एवं सहायता की संख्या में निरन्तर कमी आई है। पिछले सप्ताह में जहाँ प्रतिदिन करीब 4 हजार लोग सी.एम. हेल्पलाईन 181 पर अपनी जरूरतों एवं सहायता के लिए सम्पर्क कर रहे थे वहीं अब यह संख्या मात्र 1 हजार तक सिमट गई है।

सी.एम. हेल्पलाइन नम्बर 181 पर सम्पर्क करने वाले 8 लाख 28 हजार 947 लोगों को भोजन, राशन, दवाओं तथा अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई है। सी.एम. हेल्पलाइन नम्बर 181 पर अब तक भोजन एवं राशन संबंधी 6 लाख 66 हजार 328, दवाइयों संबंधी 41 हजार 232 तथा अन्य प्रकार की 1 लाख 21 हजार 387 समस्याओं की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई कर सहायता मुहैया कराई गई।

बाँस वन विदोहन और अध्ययन के लिए समिति गठित

भोपाल। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख श्री राजेश श्रीवास्तव ने बालाघाट जिले में बाँस वनों के विदोहन और अन्य वानिकी कार्यों के प्रभावों के अध्ययन के लिये समिति गठित की है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) की अध्यक्षता में गठित समिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैम्पा, विकास और उत्पादन, मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वन मंडल अधिकारी सामान्य वन मंडल दक्षिण बालाघाट और वन मंडल अधिकारी उत्पादन वन मंडल दक्षिण बालाघाट को सदस्य नामांकित किया गया है। समिति एक माह के भीतर बाँस से संबंधित रणनीति और वन बढ़ाने वाले उपायों पर अपना प्रतिवेदन देगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पहली बार वनों की उत्पादकता बढ़ाने और जिन क्षेत्रों में वन कम हो रहे हैं वहां की स्थिति का अध्ययन कर रणनीति बनाने के उद्देश्य से यह समिति गठित की गई है। सबसे पहले बाँस उत्पादन की रणनीति तैयार करने के लिए बालाघाट जिले का चयन किया गया है। समिति चयनित वन मंडलों में चयन सह सुधार कार्य योजना के तहत विदोहन के बाद की स्थिति का आकलन करेगी। साथ ही पुनरूत्पादन और अन्य वन बढ़ाने वाले कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन कर भविष्य में प्रदेश के लिये उत्तम वन क्षेत्र की बनाने रणनीति तैयार करेगी।

किसान उत्पादक समूहों का अधिक से अधिक गठन करें : मंत्री श्री पटेल

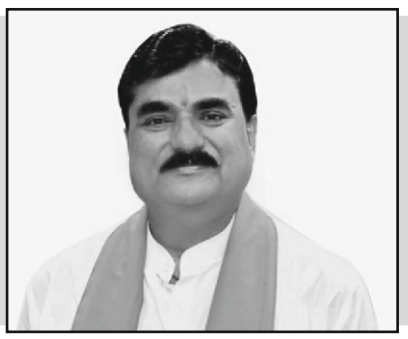

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने मंत्रालय में कृषि विभाग की समीक्षा की। उन्होंने आगामी खरीफ सीजन को दृष्टिगत रखते हुए किसानों के हित में सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। मंत्री पटेल ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान उत्पादक समुहों का गठन किया जाना सुनिश्चित करें।

मंत्री श्री पटेल ने समीक्षा करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के के सिंह एवं संचालक कृषि श्री संजीव सिंह को निर्देशित किया कि आगामी खरीफ के सीजन को दृष्टिगत रखते हुए खाद एवं बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने खरीफ सीजन की विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य तत्काल जारी करने, खाद, बीज एवं कीटनाशक के गुण नियंत्रण हेतु नियमानुसार सैंपल लेने, परीक्षण कराने तथा अमानक पाए जाने पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री पटेल ने दिए जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान करते हुए किसानों को सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश कृषि उत्पादन आयुक्त को दिए। उन्होंने डालर चने को अधिसूचित कराया जाकर मान्यता दिए जाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने , काला चना के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी निर्देश दिए।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा संचालित किसानों के हित में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो भी सामग्री वितरित कराई जाती है, वह जनप्रतिनिधियों के साथ समारोह पूर्वक वितरित कराई जाए एवं उसकी वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रत्येक विकासखंड में मृदा परीक्षण करने हेतु बनाई गई मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशालाओं को चालू करने, कोदो कुटकी को बढ़ावा दिया जाये। बैठक में कृषक प्रशिक्षण केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करते हुए आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने तथा कृषकों को प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए।

शासन के सहयोग से फिर से छोटे-छोटे काम धंधे होंगे शुरू : मुख्यमंत्री

सरकार देगी 10 हजार रुपए तक का लोन

भोपाल। ममुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में छोटे–छोटे काम धंधे करने वाले नागरिक प्रभावित हुए हैं। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ऐसे लोगों का स्व–रोजगार फिर से शुरू करायेगी। गली–मोहल्लों में फेरी लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले नागरिकों को सरकार अपनी गारंटी पर 10 हजार रुपए तक का लोन देगी, जिसका 7 प्रतिशत ब्याज केंद्र सरकार वहन करेगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए बैंकों से टायअप कर लिया गया है। वही ऐसे छोटे–छोटे काम धंधे करने वाले नागरिकों को संबल योजना में भी शामिल कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान इंदौर के अभय प्रशाल में पथ विक्रेता निधि, जीवन शक्ति योजना और प्रवासी मजदूर रोजगार समीक्षा योजना के कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सेतु योजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा की कोरोना महामारी के बीच नागरिकों को राहत देते हुए विभिन्न योजनाओं में आज तक 26 हजार करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में डाले गए है। इनमें प्रवासी मजदूरों को भी शामिल किया गया है। इतना ही नहीं अब 100 रुपए बिजली के बिल के स्थान पर 50 रुपए और जिनके 400 रुपए बिजली के बिल आते थे, उन्हें सिर्फ 100 रुपए बिजली का बिल भरना होगा। कार्यक्रम में महू विधायक श्रीमती उषा ठाकुर, इंदौर विधायक श्री रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक श्री महेंद्र हार्डिया, सुदर्शन गुप्ता, पीएस संजय शुक्ला, इंदौर कमिश्नर डॉ. पंकज शर्मा, जनसम्पर्क आयुक्त डॉ. सुदाम खाडे, इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रोजगार सेतु से प्रवासी मजदूरों को मिलेगा कौशल का काम

अभय प्रशाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रोजगार सेतु योजना के हितग्राही, प्रधानमंत्री पथ विक्रेता और जीवन शक्ति योजना में हितग्राहियों को प्रमाण–पत्र भी वितरित किए। इस दौरान उन्होंने पुणे में 4 हजार रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करने वाले अमित वाघे को रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से सिक्यूरिटी गार्ड के रोजगार का प्रमाण–पत्र प्रदान किया। अमित को अब 8 हजार रुपए प्रतिमाह का वेतन मिलेगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में काम करने वाले वीरेंद्र को भी इंदौर में काम मिल गया है। अब वीरेंद्र 8 हजार रुपए का मासिक वेतन पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जीवन शक्ति योजना के तहत सुरभि दोषी को प्रमाण–पत्र प्रदान किया। सुरभि ने योजना के तहत मास्क बनाकर सफाई कर्मियों को प्रदान किए थे। वही माँ संतोषी स्व–सहायता समूह की रीना प्रजापति को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 50 हजार रुपए का चेक प्रदान किया। इन्होंने भी समूह के माध्यम से मास्क बनाकर वितरित किए थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 3 योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण–पत्र वितरित किए।

कल स्वच्छ बनाया था, अब स्वस्थ्य बनाएंगे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में पार्श्व गायक शान के गाने का रिमोट बटन दबाकर शुभारंभ भी किया। इस दौरान उन्होंने ने कहा कि विश्वास और हिम्मत के दम पर फिर से इंदौर दौड़ेगा। कल स्वच्छ बनाया था, अब स्वस्थ्य बनाएंगे। इंदौर, इंदौर जीतेगा इंदौर। कार्यक्रम का स्वागत संबोधन नगर निगम महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ ने दिया। इस दौरान प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी और प्रदेश के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी संबोधित किया।

दुग्ध उत्पादकों, किसानों को के.सी.सी. देने का अभियान प्रारंभ

अभियान 31 जुलाई तक चलेगा

भोपाल। राज्य के समस्त दुग्ध उत्पादकों, किसानों को 31 जुलाई तक किसान क्रेडिट कार्ड प्रदाय करने का अभियान चलाया जा रहा है। दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कम्पनियों के दुग्ध उत्पादक, किसान योजना से लाभान्वित होंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज और वित्त मंत्री द्वारा कोविड–19 से उत्पन्न लॉकडाउन की स्थिति से निपटने के लिये किसान क्रेडिट योजना में दुग्ध उत्पादकों, किसानों को जोड़ने के दिये निर्देशों के अनुक्रम में अभियान चलाया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड से कार्यशैली पूंजी, मार्केटिंग आदि की आवश्यक्ताओं की पूर्ति दुग्ध उत्पादक, किसानों की हो सकेगी। केसीसी के अन्तर्गत ऋण पर किसानों को 2 प्रतिशत की छूट ओर समय पर भुगतान करने पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग श्री जे.एन.कन्सोटिया ने बताया कि एक जून से प्रारंभ हुए अभियान में प्रदेश के ऐसे सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड दिये जायेंगे जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और उनके पास केसीसी नहीं है। जिन भूस्वामि किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और वह दुग्ध उत्पादक भी है, वह अपने के.सी.सी. की लिमिट को बढ़वा सकते है परन्तु ब्याज की छूट 3 लाख रूपये की सीमा तक ही रहेंगी। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 1 लाख 60 हजार तक की सीमा तक की राशि बिना गारंटी के क्रेडिट कार्ड पर ली जा सकती है और दुग्ध उत्पादक किसानो द्वारा दुग्ध संघों को सीधा दुग्ध प्रदाय करने पर यह सीमा बिना गारंटी पर 3 लाख रूपये तक रहेंगी।

दुग्ध उत्पादको,किसानों से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये दुग्ध संधों द्वारा 15 जून तक क्रेडिट कार्ड फार्म भरवा कर बैंक शाखा को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए देना है। अपर मुख्य सचिव श्री कंसोटिया ने बताया कि सभी जिला कलेक्टर्स, योजना के क्रियान्वयन से जुड़े बैंकर और दुग्ध संधों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

प्रदेश में 2 लाख 57 हजार दावेदारों को उनकी काबिज भूमि के वन अधिकार पत्र वितरित

लम्बित दावों के ऑनलाइन निराकरण के लिये एम.पी. वनमित्र पोर्टल

भोपाल। प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक 6 लाख 27 हजार से ज्यादा दावे प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2 लाख 68 हजार से अधिक दावे मान्य किये गये हैं। मान्य दावों में से 2 लाख 57 हजार दावेदारों को उनकी काबिज भूमि के वन अधिकार पत्र (पट्टे) वितरित किये जा चुके हैं। शेष 10 हजार से अधिक मान्य दावों के अधिकार प्रमाण–पत्रों के वितरण की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में वन अधिकार के 3 लाख 60 हजार से अधिक दावे विभिन्न कारणों से निरस्त हुए हैं। इन्हीं निरस्त दावों का पुनरू परीक्षण एम.पी. वनमित्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

अधिनियम के दावों का ऑनलाइन निराकरण एम.पी. वनमित्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इस पोर्टल में अभी तक 20 हजार 794 ग्राम पंचायतों के सचिवों की प्रोफाइल अपडेट की जा चुकी है और 35 हजार 724 दावेदारों द्वारा अपने नये एवं पूर्व के निरस्त दावों के पुनःपरीक्षण के लिये ऑनलाइन दावे प्रस्तुत किये गये हैं। इन दावों का ग्राम वन अधिकार समितियों, उप खंड स्तरीय समितियों एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समितियों द्वारा निराकरण किया जा रहा है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दावों के निराकरण के लिये रोडमेप तैयार किया गया है। प्रदेश में 30 जून 2020 तक दावों का निराकरण किये जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है।

राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी पात्र वनवासी दावेदार अपने वन अधिकार के हक से वंचित न हो। दावेदार को अपने दावों के समर्थन में लगाये जाने वाले दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिये वन विभाग एवं राजस्व विभाग को निर्देश दिये गये हैं। एम.पी. वनमित्र पोर्टल के माध्यम से दावों का निराकरण करते समय दावेदारों को भी पर्याप्त सुनवाई के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे है। प्रदेश में वन अधिकार के दावों का निराकरण अभियान के रूप में किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना

27 हजार 281 विद्यार्थियों की 18 करोड़ 88 लाख की फीस सरकार ने जमा की

भोपाल। मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत 27 हजार 281 विद्यार्थियों की 18 करोड़ 88 लाख 24 हजार रुपये की फीस सरकार ने जमा करवायी है। यह सभी विद्यार्थी असंगठित कर्मकारों के बच्चे हैं। यह योजना मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शैक्षणिक सत्र 2018–19 में शुरू की थी।

योजना अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा के 1500 विद्यार्थियों की एक करोड़ 88 लाख 97 हजार 321, आईआईटी, एनआटी के 2 विद्यार्थियों की एक लाख 78 हजार 700, क्लैट–एन.एल.आई.यू. के 9 विद्यार्थियों की 19 लाख 55 हजार 500, मेडिकल (नीट) में 19 विद्यार्थियों की एक करोड़ 70 लाख 77 हजार, उच्च शिक्षा में 23 हजार 896 विद्यार्थियों की 13 करोड़ 78 लाख 78 हजार 953 और अन्य पाठ्यक्रमों के 1855 विद्यार्थियों की एक करोड़ 28 लाख 36 हजार 764 रुपये की फीस सरकार द्वारा जमा करवायी गयी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना) असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत माता–पिता के विद्यार्थियों को निरूशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गयी। योजना में तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है।

मानसून सीजन में खतरनाक हो सकते हैं बिजली के झटके

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से बारिश (मानसून) में विद्युत सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की अपील की है। बिजली के झटके से मामूली कष्ट से लेकर बुरी तरह जलना और ह्रदयगति रूकने जैसी घटनाएँ हो सकती हैं। बिजली झटके के शिकार व्यक्ति को जलने, नाड़ी धीमी पड़ने, सांस लेने में तकलीफ होने और बेहोश होने तक की भी स्थिति आ सकती है। बिजली का झटका खराब उपकरण, क्षतिग्रस्त तार या एक्सटेंशन लीड, पानी के संपर्क में आया हुआ बिजली का उपकरण, घर की दोष पूर्ण वायरिंग से लग सकता है।

वायरिंग लाइसेंसधारी ठेकेदार द्वारा ही करवायें। जिन साकेटों तक छोटे बच्चों की पहुंच हो सकती है, वहां साकेट कवर लगायें। बिजली के जो उपकरण लगातार प्रयोग में न हों, उनके स्विच बंद कर दीजिये। आईएसआई निशान वाले ही बिजली के उपकरणों का प्रयोग सुनिश्चित करें। बिजली का प्लग निकालते या लगातें समय हाथ गीले न हों। क्षतिग्रस्त तारों वाले बिजली के उपकरणों का प्रयोग न करें। प्रयोग में लाए जा रहे बिजली के सभी उपकरणों की नियमित रूप से जांच करें। क्षतिग्रस्त सॉकेटों, एडेप्टरों और स्विच का प्रयोग न करें। बिजली संबंधी कोई मरम्मत कराई जा रही हो तो मेन स्विच को हमेशा बंद रखें। स्वयं मरम्मत का कार्य तभी करें जब आप इसके बारे मे जानते हों। बरसात के दौरान, खुले स्थान में बिजली के उपकरण न चलाएं। पावर सप्लाई बंद करने के बाद करंट लगे व्यक्ति की सांस और नाड़ी की जांच की जा सकती है और उसे आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा दी जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो इसके शिकार व्यक्ति को कृत्रिम श्वांस दें। इससे व्यक्ति के बचने के अवसर बढ़ सकते हैं। यदि इस कार्यावधि के बारे में सुनिश्चित नहीं है तो कृपया फोन निर्देशों के लिए एम्बुलेंस कार्मिकों से पूछताछ करें। अगर रोगी सांस ले रहा है तो एम्बुलेंस आने तक उससे बातचीत करते रहें। पीड़ित को हिलाए/डुलाएं नहीं। घावों और जले हुए स्थानों को ऐसी पट्टियों से ढकें जो उस पर न चिपकें। जले स्थानों पर कभी भी किसी मरहम या तेल का प्रयोग न करें।

बचाव के उपाय

बिजली का झटका लगने पर घर की मुख्य पावर सप्लाई को तुरंत बंद कर दें। चूंकि मानव शरीर बिजली का अच्छा संवाहक है, इसलिए करंट लगे व्यक्ति को पावर बंद होने तक दूसरे व्यक्तियों द्वारा नहीं छुआ जाना चाहिए ताकि वे स्वयं करंट से बचे रहें। तुरंत आपातकालीन सेवा की सहायता लें और उन्हें विद्युत दुर्घटना के बारे में बताएं।

विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को 281 करोड़ का ई-भुगतान

सीधे हितग्राहियों के खातों में पहुंची राशि

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा 12 प्रकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं के 46.92 लाख से अधिक पेंशनधारी हितग्राहियों को 600 रूपये प्रति हितग्राही के मान से माह मई 2020 की पेंशन राशि 281 करोड 53 लाख रूपये का एकमुश्त ई–भुगतान सिंगल क्लिक पर किया गया।

सामाजिक न्याय एवं निरूशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 15 लाख 69 हजार 627 हितग्राहियों को 94.18 करोड, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के 5 लाख 36 हजार 412 हितग्राहियों को 32.18 करोड़, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन के 99 हजार 924 हितग्राहियों को 5.99 करोड, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन के 57 हजार 838 हितग्राहियों को 3.47 करोड, मानसिक रूप से अविकसित / बहुविकलांग को आर्थिक सहायता के 75 हजार 530 हितग्राहियों को 4.53 करोड एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत निराश्रित वृद्ध, कल्याण, परित्यक्ता, दिव्यांग, शिक्षा प्रोत्साहन,अविवाहिता महिला वर्ग में 23 लाख 52 हजार 929 हितग्राहियों के खातों में 141.18 करोड राशि ट्रांसफर की गई।

जीवन शक्ति योजना बनी महिलाओं के लिए रोजगार का माध्यम

भोपाल। कोरोना संकट काल में जहां एक ओर लॉकडाउन की परिस्थितियां निर्मित हुई, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी जाने लगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिहं चौहान ने इस स्थिति में प्रदेश की जनता के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये। आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने के साथ विशेष कर महिलाओं के लिये घर बैठे रोजगार देने के लिये जीवन शक्ति योजना लागू की। दोहरी लाभ वाली इस योजना योजना में एक तरफ बड़ी संख्या में महिलाओं को मास्क बनाने का काम सौंपा, वहीं दूसरी तरफ कोरोना से बचाव के लिये आम आदमी को सस्ती दरों पर मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई जीवन शक्ति योजना में शहरी महिला उद्यमियों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। योजना में शामिल होने के लिये बनाये गये पोर्टल पर 10 हजार से अधिक शहरी महिला उद्यमियों ने पंजीयन करवाया है। पंजीकृत महिलाओ को 2 करोड़ से अधिक राशि के लगभग 20 लाख कपड़े के मास्क बनाने के आर्डर दिये जा चुके हैं। महिलाओं द्वारा अब–तक 9 लाख 36 हजार से अधिक मास्क बनाकर दिये जा चुके हैं। शासन द्वारा निर्धारित प्रति मास्क की दर 11 रूपये के मान से महिला उद्यमियों को 8 लाख 65 हजार 609 मास्क के लिए 95 लाख 21 हजार 699 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जीवन शक्ति पोर्टल में शहरों की उद्यमी महिला पंजीयन करवाकर मास्क का निर्माण प्रारंभ कर सकती हैं। महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क शासन द्वारा निर्धारित दर पर जिला स्तर पर खरीदे जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नम्बर 0755–2700880 पर सम्पर्क कर सकतें हैं।

मनरेगा में रोजगार मिलने से मजदूरों का जीवन यापन हो गया आसान

भोपाल। मजदूरों को अपने गाँव में ही काम मिलता रहे तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दमोह जिले की ग्राम पंचायत सेमरा लखरौनी के निवासी हरिदास पाल और उनके भाई झलकन की कहानी कुछ इस तरह की है। इन दोनों को परिवार सहित मनरेगा में रोजगार मिलने से जीवन यापन अब आसान हो गया है।

हरिदास पाल पिछले पाँच साल से धार जिले के पीथमपुर में एक दवा कंपनी में काम कर रहा था और इसका भाई अहमदाबाद की एक दवा कंपनी में काम करता था। मार्च महीने में कोरोना महामारी के कारण दोनों अपने घर सेमरा लखरौनी आ गए। एहतियात के तौर पर 14 दिन तक क्वारेंनटाईन किया गया। इस अवधि के बीत जाने के बाद इन्हें रोजी–रोटी की दरकार थी। ऐसे में गाँव के जनप्रतिनिधि ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रमिकों को जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा से रोजगार दिलाने की बात कही है, तो ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक से सम्पर्क कर तुम लोगों को काम मिल सकता है। दोनों भाईयों ने रोजगार सहायक से सम्पर्क किया। कुछ दिन बाद नवीन जॉब कार्ड के साथ स्थानीय स्तर पर ही कपिलधारा कूप पर कार्य करने के लिए उन्हें एवं उनके परिवार के सदस्यों को मजदूरी पर रख लिया गया। ग्राम पंचायत में काम मिलने से उनका जीवन यापन आसान हुआ। हरिदास पाल का कहना है कि ऐसे ही गाँव में काम मिलता रहेगा तो फिर हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

प्रदेश में 15 लाख 65 हजार तेंदूपत्ता संग्रहित

भोपाल। तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य इस वर्ष अब तक 96 प्रतिशत पूरा हो चुका है। निर्धारित 16.29 लाख मानक बोरा के संग्रहण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 15 लाख 65 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित हो चुका है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 2500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। इस सीजन में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को मजदूरी के रूप में 407 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी।

संग्रहण वर्ष 2020 में अनेक वनवृत्त में लक्ष्य से अधिक संग्रहण हुआ है। उत्तर बैतूल में लगभग 130 प्रतिशत, दक्षिण में 123, पश्चिम बैतूल में 109 प्रतिशत, भोपाल के औबेदुल्लागंज में 117 प्रतिशत, सीहोर में 105 प्रतिशत, छतरपुर में 100 प्रतिशत और पश्चिम छिन्दवाड़ा में 108 प्रतिशत, श्योपुर में 102 प्रतिशत, अलीराजपुर में 162, धार में 161, इंदौर में 124, झाबुआ में 172, उत्तरी मंडला में 100, पश्चिमी मंडला में 99.53 प्रतिशत, जबलपुर में 103 प्रतिशत, बड़वानी में 107 प्रतिशत, बुरहानपुर में 121 प्रतिशत, खंडवा 118, खरगोन 141, सेधुआ 151, सतना 104, उत्तर सिवनी 115, नरसिंहपुर 110, गुना 119, शिवपुरी 100, देवास 129, रतलाम 160 और उज्जैन में कुल लक्ष्य का 115.14 प्रतिशत संग्रहण हुआ है। इसके अलावा अधिकांश अन्य वनवृत्त भी लक्ष्य के करीब हैं।

विकास और पर्यावरण में संतुलन आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर वृहद वृक्षारोपण का सैद्धांतिक शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि यह धरती केवल मनुष्यों की नहीं है, अपितु इस पर पशु–पक्षी, कीट–पतंगे, नदी–तालाब, समुद्र आदि सभी का अधिकार है। विकास की अंधी दौड़ में मनुष्य ने प्रकृति का अंधाधुंध शोषण किया। जंगलों का सफाया किया। कारखानों के जहरीले उत्सर्जन ने वातावरण को प्रदूषित किया। वहीं खेती में रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग ने जल एवं खाद्य साम्रग्री को दूषित कर दिया। वस्तुतरू यह विकास नहीं विनाशकारी है। विकास और पर्यावरण में संतुलन परम आवश्यक है।

यदि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ लगाना होंगे। पेड़ न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं, हमें भोजन प्रदान करते हैं अपितु भूमि का जल स्तर बढ़ाते हैं तथा जल को संग्रहित करके रखते हैं। पेड़ों के कारण ही नदियों में जल बहता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज सुभाष मंच हरदा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित वृहद वृक्षारोपण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सैद्धांतिक शुभारंभ किया तथा इसके पश्चात संस्था के सदस्यों को वीसी के माध्यम से संबोधित भी किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री कमल पटेल तथा हरदा जिले से वीडियो कान्फ्रेंसिंग में संस्था के संयोजक श्री गौरीशंकर मुकाती आदि उपस्थित थे।

दो लाख 57 हजार पौधे लगाये जायेंगे

वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत हरदा, खण्डवा, सीहोर एवं होशंगाबाद जिले की विभिन्न नदियों के किनारे 2 लाख 57 हजार पौधे लगाये जायेंगे। हरदा जिले के टिमरनी, रहटगांव, सिराली एवं हंडिया में 603 किसानों द्वारा 1 लाख 85 हजार पौधे, खण्डवा जिले के विकासखंड हरसूद के विभिन्न ग्रामों में 218 किसानों द्वारा 50 हजार पौधे, सीहोर जिले के नसरूल्लागंज में 15 किसानों द्वारा 5 हजार पौधे, होशंगाबाद के इटारसी में 30 किसानों द्वारा 12 हजार पौधे तथा देवास जिले के खातेगांव में 5 हजार पौधे लगाये जाएंगे।

संस्था का प्रयास सराहनीय

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सुभाष मंच हरदा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नहरों के किनारे वृहद वृक्षारोपण का कार्य अत्यंत सराहनीय है। इसके लिये संस्था प्रमुख श्री मुकाती एवं उनकी टीम बधाई एवं धन्यवाद के पात्र हैं।

कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि वृहद वृक्षारोपण के अंतर्गत इन चारों जिलों की नर्मदा, केवलारी, रूपारेल, घोड़ापछाड़, अजनाल, मटकुल, माचक, देदली, सुकनी आदि नदियों के किनारे बड़ी संख्या में वहां के किसानों द्वारा फलदार वृक्ष लगाये जायेंगे। इन वृक्षों की देखभाल किसान करेंगे तथा उनके फल भी वे प्राप्त करेंगे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयास से हरदा क्षेत्र में किसानों द्वारा हजारों क्विंटल मूंग की फसल ली गई है। इसके लिये उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार माना।

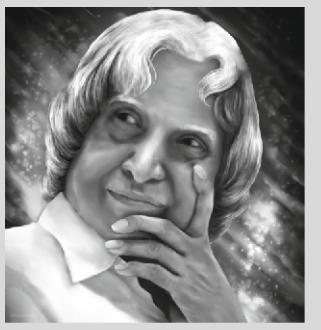

तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुँच जाओ– यही, अद्वितीय हो तुम। जिन्दगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो, और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ रहो।

— अब्दुल कलाम

किसानों और मजदूरों को दी गई राशि से मिलेगा अर्थव्यवस्था को बल

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संकट के इस दौर में किसानों और मजदूरों को विभिन्न कार्यों और योजनाओं का लाभ दिये जाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को काफी बल मिलेगा। मध्यप्रदेश सरकार सभी वर्गों को राहत देने के लिये संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान का मानना है कि किसानों को गेहूँ उपार्जन के किये गये भुगतान के अलावा फसल बीमा योजना की राशि के भुगतान, श्रमिकों को बड़ी संख्या में मनरेगा के कार्यों से जोड़ने, पंच परमेश्वर योजना के क्रियान्वयन और नगरों में 830 करोड़ रूपये के आवंटन के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। प्रदेश में इस वर्ष किसानों ने कोरोना के संकट के बाद भी अपनी मेहनत से उगाए गेहूँ की उपार्जन व्यवस्था का लाभ लिया। राज्य सरकार द्वारा की गई बेहतरीन व्यवस्थाओं से उपार्जन कार्य में बहुत अच्छी सफलता मिली है। गेहूँ का जो स्टॉक हुआ है, उसे भारतीय खाद्य निगम की नियमित क्षमता के हिसाब से अन्य राज्यों तक पहुंचाने में डेढ़–दो साल का समय लगेगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा प्रमुख सचिव खाद्य श्री शिवशेखर शुक्ला से उपार्जन संबंधी अद्यतन जानकारी प्राप्त की। श्री शुक्ला ने बताया कि आज तक प्रदेश में 124 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन 15 लाख 54 हजार किसानों सेकिया गया है। प्रदेश में 13 लाख 05 हजार किसानों को इसके लिये 17 हजार 457 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इन किसानों में साढ़े 9 लाख छोटे और मध्यम श्रेणी के किसान शामिल हैं। इस वर्ष राज्य में अनुमानित 23 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि किसानों को उपार्जित गेहूँ की राशि का भुगतान करने का कार्य भी पूरी तरह शीघ्र सम्पन्न किया जाए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में बताया गया कि प्रदेश में 110 लाख 40 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का परिवहन किया जा चुका है। यह उपार्जित गेहूँ का 90 प्रतिशत है। भारतीय खाद्य निगम के लिये भी यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। प्रदेश में हुये बम्पर गेहूँ उत्पादन को अन्य जरूरतमंद राज्यों तक पहुंचाने के लिये पूरी व्यवस्था जमानी होगी। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने जानकारी दी कि प्रदेश में गेहूँ के भंडारण की तुलना रेलवे रेक से करें तो 5 हजार रेक के बराबर गेहूँ का भंडारण हुआ है। यह कुल 6 लाख 25 हजार ट्रक क्षमता के बराबर है।

पलाश और कुसुम लाख के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के पालन में राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा पलाश और कुसुम लाख के लिये निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की गई है। अब संग्राहकों से पलाश लाख 150 रूपये प्रति किलो के बजाय 200 रूपये प्रति किलो और कुसुम लाख 230 रूपये की जगह 275 रूपये प्रति किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से खरीदा जायेगा।

राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संग्रहण वर्ष 2020 के लिये पुनर्निधारित दरें एवं उनमें हुई बढ़ोत्तरी इस प्रकार हैं :

क्रं	लघु वनोपज	पुरानी दर राशि रूपये	नवीन दर राशि रूपये	बढ़ोत्तरी का प्रतिशत
1.	अचार गुठली	109	130	19%
2.	पलाश लाख	130	200	53%
3.	कुसुम लाख	203	275	35%
4.	हर्रा	15	20	33%
5.	बहेड़ा	17	25	47%
6.	बेल गुदा	27	30	11%
7.	चकोड बीज	14	20	42%
8.	शहद	195	225	15%
9.	महुआ फूल	30	35	16%
10.	महुआ बीज	30	35	16%
11.	करंज बीज	35	40	14%
12.	नीम बीज	23	30	30%
13.	साल बीज	20	20	—
14.	नागरमोथा	27	35	29%

गेहूं के शत-प्रतिशत सुरक्षित भंडारण का कार्य सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की वीडियो कांफ्रेंस से कलेक्टर्स–कमिश्नर्स से चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से जिला कलेक्टरों और कमिश्नर्स से विभिन्न जिलों में हुई बारिश के संदर्भ में गेहूँ के शतप्रतिशत सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा एक तरफ कोविड–19 और अब निसर्ग तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश के कारण कुछ स्थानों पर खुले में रखे गेहूँ का सुरक्षित भंडारण एक चुनौती है। हालांकि बहुत कम मात्रा में गेहूँ गोदामों तक न पहुंचने की बात सामने आई है, लेकिन किसानों को उनके उपार्जित गेहूँ का पूरा भुगतान किया जाएगा। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि उपार्जित गेहूँ के परिवहन का कार्य जिन जिलों में पूरा हो गया है, वहां के वाहनों को अन्य जिलों में परिवहन कार्य में संलग्न करें। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी इस अवसर पर उपस्थित थे।

गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में दूसरे क्रम पर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गेहूँ के बंपर उत्पादन और उपार्जन के लिए किसानों सहित संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में गेहूँ उपार्जन का ऐतिहासिक कार्य हुआ है। यह आज एक करोड़ 25 लाख 60 हजार मीट्रिक टन हो चुका है। पंजाब के बाद मध्य प्रदेश अभी दूसरे क्रम पर है। यह गर्व की बात है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा 26 जिलों में शत–प्रतिशत गेहूँ उपार्जन और परिवहन का कार्य विपरीत परिस्थितियों में संभव कर दिखाया गया। विपरीत परिस्थितियों में और संकट में सफलता प्राप्त करने का अपना आनंद है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कहीं भी गेहूँ खराब न हो इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए। केरल में मानसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी जहां खुले में गेहूँ रखा है उसे सुरक्षित रखने का कार्य किया जाए। जो शेष स्कंध है डनेज शीट बिछाकर रखने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए कि किसानों को उन्हें मिलने वाली राशि का भुगतान भी सुनिश्चित करें। चने के उपार्जन और परिवहन के संबंध में भी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए। तिवड़ा मिश्रित चने की अनुमति प्राप्त होने के बाद यह कार्य भी पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि अन्य विभाग के अमलों का उपयोग करते हुए, अधिकारी दल बनाकर कार्यों को पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने टिड्डी दल पर नियंत्रण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। प्रदेश के 21 जिलों में टिड्डी दल की समस्या से 18 जिले निजात पा चुके हैं। शेष तीन जिलों शिवपुरी, बैतूल, रीवा में आवश्यक उपाय अपनाए जा रहे हैं। टिड्डियों के खात्मे के लिए फायर ब्रिगेड और दवाओं के छिड़काव का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में चना, सरसों और मसूर के उपार्जन की भी व्यवस्थाएं पुख्ता रखने के निर्देश दिए।

कोरोना पर रखें नजर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस के एक संभावित पीक को देखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल सभी सावधानियां पूरी तरह बरती जाना चाहिए। जन जागरूकता अभियान निरंतर चलना चाहिए। शिक्षण संस्थाएं अभी बंद हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी कलेक्टर अपने जिलों में आर्थिक गतिविधियों के संचालन के साथ संक्रमण न हो पाए इसके लिए प्रत्येक आवश्यक उपाय लागू करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ने, जिलों के अस्पतालों में टेस्टिंग, उपचार और अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रशासनिक अमले को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संकट की स्थिति में पुलिस बल ने भी बहुत लगन से कार्य किया है। इन सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पुलिस बल को भी बधाई दी।

विपरीत स्थितियों में सफलता का आनंद

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि किसी भी नगर में संक्रमण न फैले, व्यवस्थाएं सुविचारित हों। नागरिकों और व्यापारियों को राहत दें, इसके लिये दुकानों के समय और दिन निर्धारित कर बाजारों में आवश्यक प्रबंध हों। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्दश दिए कि कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों की संख्या पर निरंतर नजर रखी जाये। यह संतोष की बात है कि अनलॉक–वन से वायरस के स्प्रेड होने की बात सामने नहीं आयी है। फिर भी सैम्पलिंग, स्क्रीनिंग के कार्य नियमित किये जाएं। प्रत्येक नागरिक जागरूक रहे। दुकानदार सेनेटाईजर की व्यवस्था रखें। मास्क के उपयोग की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी का भी पालन हो। प्रदेश में लगभग 85 हजार बैड की व्यवस्था है, ताकि किसी संकट की आशंका होने पर निपटा जा सके। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने यह सिद्ध किया है कि पॉजिटिव केस भी ठीक हो जाते हैं। अच्छी व्यवस्थाओं के फलस्वरूप ही देश में मध्यप्रदेश का रिकवरी रेट दूसरे नंबर पर है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को संकट की स्थिति में कार्य का जुनून भी होता है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में ...

मध्यप्रदेश सरकार ने गेहूँ उपर्जान के लिए प्रभावी रणनीति बनाई। पिछले वर्ष किये गये उपार्जन से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए बारदानों और भण्डारण की व्यवस्था की गई। कोरोना की विषम परिस्थिति के कारण उपार्जन कार्य देर से 15 अप्रैल से शुरू किया गया। सरकार इस बात के लिए सचेत थी कि मंदी और आवागमन बाधित होने के कारण किसानों से पिछले वर्ष की अपेक्षा कही ज्यादा उपार्जन कम अवधि मे करना होगा। सरकार द्वारा तुरंत ही अतिरिक्त बारदानों एवं भण्डारण की व्वस्था की गई। लॉकडाउन के बावजूद 25 लाख मीट्रिक टन के लिए अतिरिक्त बारदानों की व्यवस्था की गई। बारदानों के सुनियोजित प्रबंधन के फलस्वरूप लक्ष्य से अधिक इतनी बड़ी खरीदी होने के बाद भी बारदानों की कमी नहीं होने दी गई। लॉकडाउन में ही कार्य करते हुए 10 लाख मीट्रिक टन के लिए भंडारण की व्यवस्था की गई।

सबसे बड़ी चुनौती ज्यादा किसानों से कम अवधि में ज्यादा उपर्जान करना था। इसके लिए पिछले वर्ष उपार्जन केन्द्रों की संख्या 3 हजार 545 को बढाकर 4 हजार 529 केन्द्र खोले गये। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों को एसएमएस भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई ताकि एसएमएस प्राप्त किसान ही खरीदी केन्द्र पहुँचें। सही समय पर खरीदी पूर्ण करने की चुनौती को देखते हुए पहली बार यह सुविधा दी गई कि कलेक्टर स्वयं एक–एक केन्द्र पर एसएमएस संख्या निर्धारित कर सकें। किसानों को कोरोना के प्रति सजग रहने और अन्य जानकारी देने के लिए 75 लाख एसएमएस भेजे गए।

राज्य सरकार द्वारा गेहूँ उपार्जन की राशि सीधे किसानों के खातों में औसतन 7 दिवस में अंतरित की गई। अभी तक 14 लाख 19 हजार किसनों के खातों में 20 हजार 253 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। किसानों को समय से भुगतान हो सके, इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था उपार्जन अवधि के पूर्व ही सुनिश्चित की गई। जिससें कभी भी किसानों को भुगतान में विलंब की स्थिति निर्मित नही हुई।

उपार्जित गेहूँ के भंडारण और परिवहन की चुनौती का भी सफलता पूर्वक सामना किया गया। कुल उपार्जित गेहूँ में से 118 लाख मीट्रिक टन का परिवहन कर सुरक्षित भंडारण किया जा चुका है, जो कि खरीदी मात्रा का लगभग 95 प्रतिशत है। इस बार जितने किसानों ने पंजीयन कराया था उनमें से 81 प्रतिशत गेहूँ बेचने के लिए उपार्जन केन्द्रों पर आयें, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। पिछले वर्ष किसानों का टर्न आउट 48.36 प्रतिशत था जो इस बार 81 प्रतिशत रहा है। यह अभी तक का सर्वाधिक टर्न आउट है। इस बार एक और महत्वपूर्ण बात हुई है। पिछले वर्ष लघु एवं सीमांत किसानों का उपार्जन में भाग लेने का प्रतिशत केवल 40 प्रतिशत था जो बढ़कर इस बार 84 प्रतिशत हो गया है। इससे स्पष्ट है कि इस बार लघु और सीमांत किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने पर अधिक लाभ हुआ है। शासन ने 130 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता विकसित कर ली है, जो गेहूँ भंडारण के लिए शेष है, उसका भंडारण भी बहुत शीघ्र सुनिश्चित कर लिया जायेगा। गेहूँ के परिवहन में 10 हजार से अधिक ट्रकों का उपयोग किया गया है। सरकार ने 135 लाख मीट्रिक टन खरीदी के लिए बारदानों की भी व्यवस्था की है।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिये यथासंभव लोकल का प्रयोग करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश संबंधी बैठक ली

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए यथासंभव लोकल का प्रयोग करें। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन को मध्यप्रदेश की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप चलाया जाए। विशेषज्ञों का समूह बनाए जाकर उनके सुझावों के आधार पर श्आत्मनिर्भर मध्यप्रदेशश की विस्तृत योजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश संबंधी बैठक ले रहे थे। बैठक में स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस के महानिदेशक श्री आर.परशुराम, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी उपस्थित थे।

किसानों को सही दाम मिले

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिए कि किसानों को उनके उत्पादों का सही दाम मिले। कृषि विपणन को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। कृषि में विविधता आए। किसान ऐसी फसल लें जो उन्हें अच्छी आमदनी दिलवाए। एग्रीकल्चर पैटर्न को बेहतर बनाया जाए। छोटे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बढ़े।

भारत सरकार के पैकेज का पूरा लाभ लें

मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत घोषित विशेष पैकेज का पूरा लाभ प्रदेश को दिलाने के लिए तत्परता से कार्य किया जाए। छोटे कारोबारियों के लिए 10 हजार के ऋण तथा उस पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना का लाभ उन्हें दिलाया जाए।

वन एवं आदिवासियों का विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की वन संपदा तथा आदिवासी बहुलता को देखते हुए इस प्रकार की योजना बनाई जाए जो वन एवं आदिवासियों का विकास करे।

लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश कि लोकल प्रोडक्ट्स जैसे चंदेरी साड़ियां, बाघ प्रिंट आदि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गांव–गांव में छोटे एवं कुटीर उद्योग कैसे खड़े हो सकते हैं यह देखा जाए।

रीयल सिंगल विंडो बने

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा एवं नए उद्योगों की स्थापना के लिए सिंगल विंडो सिस्टम सही मायने में सिंगल विंडो बने। प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप अलग–अलग सैक्टर में उद्योग स्थापित किए जाएं।

ग्रामीण विकास की अवधारणा बदलें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें ग्रामीण विकास की अवधारणा को बदलना होगा। ग्रामों का विकास इस प्रकार किया जाना होगा, जिससे वहां ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण हो और ग्रामीणों को शहर न जाना पड़े।

शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करना होगा, जिससे गाँवों में ही अच्छी शिक्षा व अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके। ग्रामों के समूह बनाकर उनके बीच उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता के विद्यालय खोले जाएं।

सुशासन संस्थान को आदर्श बनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान को आदर्श बनाया जाए तथा यह सुशासन, नीति एवं योजनाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाए। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के देश–दुनिया के विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएं।

पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हँसेंगे, फिर वो आप से लड़ेंगे, और तब आप जीत जायेंगे।

– महात्मा गांधी

मुख्यंत्री द्वारा घोषित रियोयतों से बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी 1150 करोड़ की राहत

ऊर्जा विभाग द्वारा आदेश जारी

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉकडाउन के कारण हुई परेशानी के मद्देनजर बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये की गई घोषणाओं के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। इससे विभिन्न वर्ग के लगभग एक करोड़ 11 लाख बिजली उपभोक्ताओं को करीब 1150 करोड़ रूपये की राहत मिलेगी।

प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने प्रबंध संचालक एमपी पॉवर मेनेजमेंट कंपनी और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालकों को रियायतों के संबंध में जारी आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के निम्नदाब गैर–घरेलू एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा उच्च टैरिफ एचव्ही–3 उपभोक्ताओं के माह अप्रैल के साथ ही मई एवं जून 2020 के विद्युत देयकों में स्थायी प्रभार की वसूली को स्थगित कर दिया गया है। स्थगित राशि की वसूली अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के विद्युत देयकों के नियमित भुगतान के साथ 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के की जाएगी। इस निर्णय से करीब 12 लाख उद्यमियों को लगभग 700 करोड़ रुपये की तात्कालिक राहत मिलेगी।

संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रूपये या उससे कम आये थे तथा मई, जून, जुलाई में भी 100 रूपये से कम आयेंगे, उनसे मई, जून, जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रूपये महीने का भुगतान लिया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से लगभग 63 लाख हितग्राहियों को 100 करोड़ रूपये का लाभ होगा।

ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपये से कम आए थे किन्तु मई, जून और जुलाई माह में 100 रुपये से अधिक परंतु 400 रुपये से कम आए हैं या आएंगे, तो उनसे मई, जून और जुलाई माह के बिल की राशि के स्थान पर सिर्फ 100 रुपये प्रतिमाह लिया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 28 लाख हितग्राहियों को 150 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल माह अप्रैल में 100 रूपये से अधिक परन्तु 400 रूपये या उससे कम आए थे, उनके मई, जून और जुलाई माह में देयक राशि 400 रूपये से ज्यादा आने पर उनसे इन तीन माहों में देयक की राशि का मात्र 50 प्रतिशत भुगतान लिया जाएगा। शेष बिल की राशि की जाँच के उपरांत निर्णय लिया जाएगा।

स्व–रोजगार के लिए 1743 स्व–सहायता समूहों को 20 करोड़ से अधिक का लोन

भोपाल। दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में स्व–रोजगार स्थापना के लिए 1743 महिला स्व–सहायता समूहों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से जोड़ कर 20 करोड़ 75 लाख रुपये का लोन उपलब्ध करवाया गया है। प्रदेश में 52 जिलों के 120 नगरीय निकायों में अभी तक 25 हजार 478 स्व–सहायता समूह गठित किये जा चुके हैं।

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि ने जानकारी दी है कि वर्ष 2019–20 में 3308 स्व–सहायता समूहों का गठन किया गया है। इनमें से 2377 समूहों को 10–10 हजार रुपये प्रति समूह के मान से कुल 2 करोड़ 37 लाख रुपये की आवर्ती निधि दी गयी है। समूहों को मिले लोन के प्रचलित ब्याज दर 7 प्रतिशत से ऊपर की दर की राशि ब्याज अनुदान के रूप में वदसपदम च।प्। च्वतजंस के माध्यम से प्रतिमाह स्व–सहायता समूहों के खाते में (डी.बी.टी.) जमा की जा रही है। हर माह लगभग 10 लाख रुपये समूहों के खाते में डीबीटी किये जा रहे हैं।

समूहों को उपलब्ध करवाई जा रही इस राशि से महिलाओं को स्व–रोजगार आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलती है। इन समूहों द्वारा तैयार सामग्रियों के विक्रय के लिये बाजार भी उपलब्ध करवाया जाता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जीवन शक्ति योजना में मास्क बनाने का काम भी इन महिला स्व–सहायता समूहों को दिया गया है।

संग्राहकों से 1582 क्विंटल महुआ फूल खरीदा गया

भोपाल। राज्य लघु वनोपज संघ ने संग्रहण वर्ष 2020 में संग्राहकों से बढ़ी दर पर अब तक 1582 क्विंटल महुआ फूल खरीदा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 35 रूपये प्रति किलो की दर से खरीदे गए फूल से संग्राहकों को 55 लाख 37 हजार रूपये की आय हुई है। उल्लेखनीय है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गत माह महुआ फूल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रूपये प्रति किलो से बढ़ाकर 35 रूपये करने के निर्देश दिये थे।

महुआ फूल का चिकित्सकीय और औषधीय रूप से काफी महत्व है। इसके फल–फूल, पत्ती, लकड़ी, सभी का प्रयोग होता है। ह्रदय, लिवर, कैंसर, अल्सर, ब्रोंकाईटिस, बुखार आदि अनेक रोगों में महुआ और महुए के फूल का उपयोग किया जाता है।

मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना हमारा संकल्प : मुख्यमंत्री

विभिन्न औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने की चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना हमारा सपना भी और संकल्प भी है और यह सपना उद्योगों की स्थापना के बगैर पूरा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि रोजगार मुहैया कराने में इंडस्ट्रीज सेक्टर अग्रणी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज इंदौर के अभय प्रशाल में विभिन्न औद्योगिक संघों के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास निगम इंदौर परिक्षेत्र के तहत 2015 से 2018 तक हुए उद्योग स्थापना के कार्य का प्रजेंटेशन भी देखा। इस दौरान उन्होंने पीथमपुर की तीन औद्योगिक इकाईयों का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर बताया कि कोरोना काल के दौरान पिछले माहों में प्रदेश को 26 हजार करोड़ रूपए के टेक्स का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिये योजनाबद्ध रूप से प्रयास किये जायेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा। पीथमपुर की दवा इंडस्ट्रीज ने अमेरिका जैसे देश को कोरोना काल में दवाइयों की सप्लाई कर देश का मान बढ़ाया है। इसके अलावा पीपीई किट के निर्माण तथा सैनिटाइजर बनाने के काम में पीथमपुर की इंडस्ट्रीज अग्रणी रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रेजेंटेशन में जब यह बताया गया कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा काम प्रारंभ कर दिया गया है, तब मुझे लगा कि जो सपने देखे थे वह साकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार हमारे कुछ मित्र कहते थे यह निवेश के सम्मेलन करने से क्या होता है। यह प्रेजेंटेशन जबाव है यह बताने के लिए कि प्रयास किए जाएं तो परिणाम आते ही हैं। इंदौर में आईटी सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों को लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि लोकल के लिए वोकल हो। मैंने निर्णय लिया है कि हर सोमवार एक घंटा उद्योगों को दूंगा। इस पर सुझाव और चर्चा होगी। इसके अलावा हर सेक्टर के उद्योगपतियों से भी चर्चा करूंगा। यह चर्चा या तो मीटिंग के माध्यम से होगी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। श्रमिक कानून में परिवर्तन किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम के कार्य को और सरल बनाएंगे। पहले उद्योगपतियों को 61 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे, हमने उसे कम कर 14 किया है और अब तो बस एक रजिस्टर ही संधारित करना पड़ता है।

कार्यक्रम में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, पूर्व मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्री रमेश मेंदोला, श्रीमती मालिनी गौड़ तथा श्री आकाश विजयवर्गीय, सुश्री उषा ठाकुर आदि मौजूद थे।

कोरोना संक्रमण से जन-सामान्य की सुरक्षा और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार की व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता

जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में आदिम–जाति कल्याण मंत्री

भोपाल। आदिम–जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से जन–सामान्य की सुरक्षा तथा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। आदिम–जाति कल्याण मंत्री आज उमरिया में जिला–स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक को संबोधित कर रही थीं। बैठक में विधायक श्री शिवनारायण सिंह भी मौजूद थे।

आदिम–जाति कल्याण मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिये और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिले के जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव लोग चिन्हित हुए हैं, वहाँ सावधानी बरती जाये। कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाये। जिन छात्रावासों एवं स्कूलों में लोगों को क्वारेंटाइन किया गया था, उन्हें सेनेटाइज कराया जाये।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को समय पर मजदूरी भुगतान हो

आदिम–जाति कल्याण मंत्री ने एक अन्य बैठक में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 71 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण किया जा चुका है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों के खातों में 11 करोड़ 62 लाख रुपये की मजदूरी का भुगतान किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को तेन्दूपत्ता संग्राहकों को मजदूरी का भुगतान समय पर किये जाने के निर्देश दिये।

कृषि मंत्री ने किसानों को दी बधाई

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि किसानों के कठोर परिश्रम से आज हमारा प्रदेश देश में गेहूँ के उपार्जन में पहले नम्बर पर आ गया है। उन्होंने बताया कि किसानों ने इस वर्ष विपुल मात्रा में गेहूँ का उत्पादन किया है। प्रदेश सरकार ने गेहूँ का 128 लाख मीट्रिक टन से अधिक का रिकार्ड तोड़ उपार्जन कर देश में पहला स्थान पाया है। अब तक गेहूँ उपार्जन में प्रथम स्थान पर पंजाब रहता आया है।

कृषि मंत्री ने प्रदेश के समस्त किसान और गेहूँ उपार्जन करने वाले अधिकारी–कर्मचारियों की टीम को इस गौरवशाली उपलब्धि के लिये बधाई दी है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों के परिश्रम से मध्यप्रदेश सरकार को लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने विश्वास जताया है कि भविष्य में भी प्रदेश के किसान इसी प्रकार से प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे।

अब तक 5 लाख 96 हजार श्रमिक वापस

भोपाल। अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल–रूम श्री आई.सी.पी. केशरी ने जानकारी दी है कि अभी तक विभिन्न प्रदेशों में फँसे मध्यप्रदेश के करीब 5 लाख 96 हजार श्रमिक वापस लाये जा चुके हैं। इनमें 137 ट्रेनों से करीब एक लाख 77 हजार और बसों से लगभग 4 लाख 19 हजार श्रमिक वापस लाये गये हैं।

आज तक गुजरात से 2 लाख 18 हजार, राजस्थान से एक लाख 30 हजार, महाराष्ट्र से एक लाख 44 हजार श्रमिक वापस लाये गये हैं। इसके अतिरिक्त गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु एवं तेलंगाना से भी श्रमिक वापस लाये गये हैं।

प्रदेश में अब तक महाराष्ट्र से 38, गुजरात से 30, हरियाणा से 15, तेलंगाना एवं पंजाब से 7–7, कर्नाटक तथा तमिलनाडु से 4–4, जम्मू, गोवा एवं केरल से 3–3 और राजस्थान तथा दिल्ली से 2–2 ट्रेन आ चुकी हैं। प्रदेश के बाहर से करीब 4 लाख 89 हजार श्रमिकों को अन्य प्रदेशों की सीमा तक बसों से पहुँचाया गया है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।